डाक पंजीयन क्रमांक - म.प्र./भोपाल/4-357/2024-26

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक

प्रकाशन दिनांक 1 जनवरी, 2025, डिस्पेच दिनांक 1 जनवरी, 2025

| वर्ष 68 | अंक 15 | भोपाल | 1 जनवरी, 2025 | पृष्ठ 08 | एक प्रति 7 रु. | वार्षिक शुल्क 150/- | आजीवन शुल्क 1500/- |

सहकारिता के नए युग की शुरुआत: 10,000 बहुउद्देशीय PACS और सहकारी समितियों का लोकार्पण

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में 10,000 नवगठित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (M-PACS), डेयरी व मत्स्य सहकारी समितियों का शुभारंभ किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के 'सहकार से समृद्धि' के मंत्र को चरितार्थ करने के लिए PACS की पहुँच हर गांव तक सुनिश्चित की जा रही है

मोदी सरकार Feasibility, Relevance, Viability and Vibrancy के साथ PACS का विस्तार कर रही है

5 साल में 2 लाख नए PACS बनाने का लक्ष्य समय से पहले होगा पूरा

कंप्यूटरीकरण से PACS की पारदर्शिता बढ़ी, जिससे सहकारिता का विस्तार हो रहा है और महिलाओं व युवाओं को रोजगार के नये अवसर मिल रहे हैं

2 लाख PACS बनने के बाद, फॉरवर्ड-बैकवर्ड लिंकेज के माध्यम से किसानों की उपज को विश्व के बाजारों तक पहुँचाना सरल हो जाएगा

मोदी सरकार हर प्राथमिक डेयरी व किसानों को माइक्रो ATM व रुपे KCC कार्ड देकर बहुत कम खर्च पर ब्रिज फाइनेंस देने का काम करेगी

तीन नई राष्ट्रीय सहकारी संस्थाओं से जुड़ PACS अब ऑर्गेनिक उत्पाद, बीज उत्पादन और निर्यात में सक्रिय होंगे, जिससे किसानों की समृद्धि सुनिश्चित होगी और सामाजिक-आर्थिक समानता का मार्ग प्रशस्त होगा

नई दिल्ली। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में 10,000 नवगठित बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS), डेयरी व मत्स्य सहकारी समितियों का शुभारंभ किया। इस अवसर पर केन्द्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी एवं पंचायती राज मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह, केन्द्रीय सहकारिता राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल और श्री मुरलीधर मोहोल और सहकारिता मंत्रालय के सचिव सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

अपने संबोधन की शुरुआत श्री अमित शाह ने 2 महापुरुषों - पंडित मदन मोहन मालवीय और पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी - की जन्मजयंती के अवसर पर दोनों महापुरुषों को श्रद्धांजलि देकर की। उन्होंने कहा कि पंडित मदन मोहन मालवीय जी भारत की आज़ादी की लड़ाई के सभी नायकों में अग्रिम स्थान रखते हैं और उन्होंने देश की आज़ादी, भारतीयता, संस्कृति और हिंदू धर्म को चेतना देने के लिए आजीवन काम किया। श्री शाह ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देश की संसद में 5 दशकों तक भारत और संस्कृति की आवाज़ बनकर संसद का मार्गदर्शन किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के रूप में अटल जी ने कई नई शुरूआत की जिनके कारण भारत आज ऊंचाइयों को प्राप्त कर सका है। श्री शाह ने कहा कि भारत को आणविक शक्ति देने और करगिल युद्ध के दौरान देश की भूमि के लिए संघर्ष करने का सिद्धांत अटल जी ने स्थापित किया। उन्होंने कहा कि अटल जी ने देश के हमारे जनजातीय भाइयों-बहनों के लिए एक अलग मंत्रालय बनाया। अटल जी ने ही स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग की शुरूआत की और देश के सभी गांवों को राज्य राजमार्ग के साथ जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरूआत की। गृह मंत्री ने कहा कि आज महान स्वतंत्रता सेनानी श्री सी राजगोपालाचारी जी की पुण्यतिथि भी है, जो हमारे वेदों, उपनिषदों और पुरातन साहित्य के ज्ञाता थे और संविधान की रचना में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि आज अटल जी की जन्म शताब्दी के दिन 10 हज़ार नई बहुद्देश्यीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (MPACS), डेयरी व मत्स्य सहकारी समितियों का शुभारंभ हो रहा है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक संयोग नहीं है क्योंकि संविधान में 97वां संशोधन अटल जी के समय में ही आया और बहुत समय से हाशिए पर पड़ी सहकारिता को अटल जी ने फिर से महत्व दिया था।

श्री अमित शाह ने कहा कि 19 सितंबर 2024 को इसी स्थान पर हमने एक SOP बनाई थी और उसके 86 दिन के अंदर ही हमने 10 हज़ार पैक्स को रजिस्टर करने का काम समाप्त कर दिया है। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की, तो उन्होंने 'सहकार से समृद्धि' का ध्रुव वाक्य दिया था। श्री शाह ने कहा कि 'सहकार से समृद्धि' तभी संभव है जब हर पंचायत में सहकारिता उपस्थिति हो और वहां किसी न किसी रूप में काम करे। उन्होंने कहा कि हमारे देश के त्रिस्तरीय सहकारिता ढांचे को सबसे ज़्यादा ताकत प्राथमिक सहकारी समिति ही दे सकती है, इसीलिए मोदी सरकार ने 2 लाख नए पैक्स बनाने का निर्णय किया था।

केन्द्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि NABARD, NDDB और NFDB ने 10 हज़ार प्राथमिक सहकारी समितियों के पंजीकरण में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के बाद सबसे बड़ा काम सभी पैक्स का कम्प्यूटराइज़ेशन करने का किया गया। उन्होंने कहा कि कम्प्यूटराइज़ेशन के आधार पर पैक्स को 32 प्रकार की नई गतिविधियों से जोड़ने का काम किया गया। उन्होंने कहा कि हमने पैक्स को बहुआयामी बनाकर और उन्हें भंडारण, खाद, गैस, उर्वरक और जल वितरण के साथ जोड़ा। श्री शाह ने कहा कि ट्रेन्ड मैनपावर न होने के कारण ये सब हम नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि इसके लिए आज यहां प्रशिक्षण मॉड्यूल का भी शुभारंभ हुआ है जो पैक्स के सदस्यों और कर्मचारियों को संपूर्ण प्रशिक्षण देने का काम करेंगे।

(शेष पृष्ठ 6 पर)

हर पंचायत में पैक्स, सभी को रोजगार एवं सुव्यवस्थित सहकारी आंदोलन ही हमारा लक्ष्य : मंत्री श्री सारंग

"सहकार से समृद्धि" राज्य स्तरीय संगोष्ठी में शामिल हुए मंत्री श्री सारंग

भोपाल : सहकारिता मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा है कि हर पंचायत में पैक्स, सभी को रोजगार और सुव्यवस्थित सहकारी आंदोलन ही हमारा लक्ष्य है। सहकारिता को आगे बढ़ाने के लिये इसका विस्तार पंचायत स्तर पर करना होगा। सहकारिता के हर एक मूल भाव को आत्मसात करते हुए देश को समृद्ध बनाना ही हमारा लक्ष्य है। पैक्स के माध्यम से हर पंचायत तक रोजगार सृजित हो, इसके लिये बहुउद्देश्यीय पैक्स की अवधारणा गठित की गयी है।

मंत्री श्री सारंग ने भोपाल के समन्वय भवन में आयोजित "सहकार से समृद्धि" राज्य स्तरीय संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम के पूर्व नई दिल्ली में केन्द्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 10 हजार नवगठित बहुउद्देश्यीय पैक्स, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों का उद्घाटन किया। कार्यक्रम से सभी प्रदेशों के सहकारिता विभाग के अधिकारी वर्चुअली शामिल हुए।

परिवार सहकारिता का उत्कृष्ट उदाहरण

मंत्री श्री सारंग ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं। समृद्ध राष्ट्र के लिये समाज को जोड़ने की जरूरत है और समाज को जोड़ने का केवल एक ही प्रकल्प है, सहकारिता। समाज का निर्माण सहकारिता के माध्यम से ही होता है। सभी की भागीदारी के साथ लक्ष्य को साधने का नाम ही सहकारिता है। परिवार सहकारिता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। रोजमर्रा की जिंदगी में भी सहकारिता के बिना कुछ नहीं हो सकता। सभी की भागीदारी महत्वपूर्ण होती है।

पैक्स के माध्यम से हों रोजगार सृजित

मंत्री श्री सारंग ने कहा कि भागीदारी और बराबरी होने से अच्छे परिणाम निकलने का प्रतिशत बढ़ जाता है। सहकारी आंदोलन को मजबूत बनाने के लिये सभी वर्ग को जुड़ना होगा। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में हर पंचायत में पैक्स का लक्ष्य पूर्ण करने में सभी की भागीदारी सुनिश्चित हो। पैक्स के माध्यम से रोजगार सृजित हों और सदस्यों को लाभ मिले। उन्होंने कहा कि पैक्स पशुपालन, मत्स्य-पालन और ऋण वितरण तक ही सीमित नहीं रहे, पैक्स पेट्रोल पम्प और गैस एजेंसी भी चलाये, जिसके पास जगह हो वह शादी हॉल, मैरिज गार्डन भी बनायें, इससे पैक्स मजबूत होगा।

संस्कार के साथ सहकारी आंदोलन

मंत्री श्री सारंग ने कहा कि अगले साल तक हर पंचायत में पैक्स हो, यही संकल्प लेने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हमारा नारा है कि बिना सहकार नहीं उद्धार और बिना संस्कार नहीं सहकार। पूर्ण अनुशासन में संस्कार के साथ सहकारी आंदोलन को मध्यप्रदेश में स्थापित करने के लक्ष्य में सभी का सहयोग आवश्यक है।

सहकारी मंथन के माध्यम से हो लक्ष्य निर्धारित

मंत्री श्री सारंग ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का भी लक्ष्य है कि रोजगार सृजित कर हर घर तक रोजगार पहुँचे। इसमें पैक्स की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। युवा साथियों के माध्यम से हम सुनिश्चित करेंगे कि पैक्स बहुउद्देश्यीय हो जाये। उन्होंने कहा कि जल्द ही हम सहकारी मंथन के माध्यम से नीचे से लेकर ऊपर तक सभी के साथ संवाद करेंगे और अगले वर्षों का लक्ष्य निर्धारित करेंगे।

उत्कृष्ट अधिकारी तैयार करें

मंत्री श्री सारंग ने कहा कि उत्कृष्ट काम करने वालों का हमेशा सम्मान होता है। इसलिये आज कार्यक्रम में भी उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया है। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से कहा कि कनिष्ठों को उत्कृष्ट काम करने के लिये तैयार करें, जिससे वे वरिष्ठों की श्रेणी तक आने पर और ज्यादा सफल हो सकें।

संभावनाएँ अनंत, तलाशने की जरूरत

अपर मुख्य सचिव सहकारिता श्री अशोक वर्णवाल ने कहा कि संभावनाएँ

अनंत हैं, तलाशने की जरूरत है। पैक्स को बिजनेस बढ़ाने और हितग्राहियों को लाभ पहुँचाने की दिशा में काम करना होगा। इसके लिये सहकारिता संस्थाओं को आपस में भी व्यवसाय करने की जरूरत है।

विमोचन

कार्यक्रम में मंत्री श्री सारंग ने सहकारी बैंकों के सुदृढ़ीकरण की मानक परिचालन प्रक्रियाओं पर केन्द्रित पुस्तक, विधि प्रक्रिया एवं सरलीकृत समाधान पर केन्द्रित पुस्तिका और सहकार से समृद्धि कार्यक्रम अंतर्गत महत्वपूर्ण गतिविधियों पर केन्द्रित ब्रोशर का विमोचन किया।

सम्मान

कार्यक्रम में सीबीएस पर काम करने वाली पूर्णत: कम्प्यूटरीकृत हो चुकी प्राथमिक कृषि सहकारी समिति नहारगढ़ (मंदसौर) के प्रबंधक श्री पवन जैन, कम्प्यूटर ऑपरेटर श्री सूरज विश्वकर्मा, मनासा (धार) के प्रबंधक श्री राधेश्याम यादव, कम्प्यूटर ऑपरेटर श्री सुनील यादव, सोनकच्छ (देवास) के प्रबंधक श्री संतोष शुक्ला, कम्प्यूटर ऑपरेटर श्री देवेन्द्र सिंह एवं अपेक्स बैंक द्वारा पूरे प्रदेश में 6 अक्टूबर से 10 दिसम्बर तक आयोजित विशेष ऋण महोत्सव में उत्कृष्ट कार्य करने हुए अधिकतम ऋण वितरित करने वाले शाखा प्रबंधकों क्रमश: श्री सुनील सिंघल, भरतपुर शाखा (उज्जैन), श्री शैलेन्द्र रावत, फ्रीगंज (उज्जैन) एवं श्री अशोक चंदेल, टी.टी. नगर (भोपाल) को भी पुरस्कृत किया। उल्लेखनीय है कि पूरे प्रदेश में अपेक्स बैंक ने निर्धारित लक्ष्य 50 करोड़ रूपए के विरुद्ध 50.13 करोड़ रुपए का ऋण इस अवधि में वितरित किया गया।

कार्यक्रम में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएँ श्री मनोज पुष्प, प्रबंध संचालक मार्कफेड श्री आलोक कुमार सिंह, उप सचिव श्री मनोज सिन्हा, महाप्रबंधक नाबार्ड श्री कमर जावेद, अपर आयुक्त श्री बी.एस. शुक्ला सहित शीर्ष सहकारी संस्थाओं के प्रबंध संचालक, सभी सहकारी संस्थाओं/बैंकों के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन श्री अरविंद बोध ने किया और प्रबंध संचालक अपेक्स बैंक श्री मनोज गुप्ता ने आभार माना।

भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड के निर्धारित उद्देश्य

नई दिल्ली। सहकारिता मंत्रालय ने बहु-राज्य सहकारी समितियां (एमएससीएस) अधिनियम 2002 के अंतर्गत भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (बीबीएसएसएल) की स्थापना की है। इसे इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड (इफको), कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड (कृभको), भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नेफेड), राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) द्वारा प्रोन्नत किया जा रहा है। भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड की आरंभिक प्रदत्त पूंजी 250 करोड़ रुपये है, जिसमें पांचों उपर्युक्त प्रवर्तकों द्वारा 50-50 करोड़ रुपये का योगदान और अधिकृत शेयर पूंजी 500 करोड़ रुपये है। भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड फसल की पैदावार में सुधार लाने और स्वदेशी प्राकृतिक बीजों के संरक्षण-संवर्धन की प्रणाली विकसित करने के लिए सहकारी समितियों के नेटवर्क द्वारा गुणवत्तापूर्ण एकल ब्रांड के बीजों का उत्पादन, खरीद और वितरण करेगी। बीबीएसएसएल कृषकों की सहायता से प्रमाणित बीजों के उत्पादन में बीज प्रतिस्थापन दर और बीजों की किस्म प्रतिस्थापन दर बढ़ाने में सहायक होगी। यह सहकारी समिति प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) के माध्यम से सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की विभिन्न योजनाओं और नीतियों द्वारा दो पीढ़ियों के बीजों के उत्पादन, परीक्षण, प्रमाणन, खरीद, प्रसंस्करण, भंडारण, ब्रांडिंग, लेबलिंग और पैकेजिंग पर ध्यान केंद्रित करेगी। प्रजनक बीज सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसंधान संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थानों, अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान (आईसीआरआईएसएटी), अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (आईआरआरआई), अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र (सीआईएमएमवाईटी) आदि से लिए जाएंगे।

भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड, सहकारी समितियों के माध्यम से भारत में गुणवत्तापूर्ण बीजों के उत्पादन बढ़ाने में मदद करेगी जिससे आयातित बीजों पर निर्भरता कम होगी। इससे उत्पादन में बढ़ोतरी होगी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा और भारत आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होगा।

भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड का पटना और भागलपुर में पूर्णकालिक संसाधन हैं। प्राथमिक से लेकर शीर्ष स्तर की सभी सहकारी समितियां इसकी सदस्य बन सकती हैं। अपनी सदस्य सहकारी समितियों के माध्यम से भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड अपना कार्य संचालित करेगी। अब तक कुल 14,816 सहकारी समितियां इसकी सदस्य बनी हैं जिनमें 418 सहकारी समितियां बिहार की हैं। जहां तक बाल्मीकि नगर का सवाल है तो पश्चिमी चंपारण जिले की 05 सहकारी समितियां भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड की सदस्य बनी हैं। समिति ने बिहार में अपना परिचालन आरंभ करने तथा बिक्री और विपणन गतिविधियों के लिए बिहार में एक अधिकारी की नियुक्ति की है।

भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (BBSSL) की समीक्षा बैठक में अमित शाह ने दिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश

नई दिल्ली।केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (BBSSL) की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर केन्द्रीय सहकारिता राज्यमंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर, सचिव सहकारिता मंत्रालय श्री मुरलीधर मोहोल, अतिरिक्त सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी, और BBSSL के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री पंकज कुमार बंसल उपस्थित रहे।

बैठक को संबोधित करते हुए श्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के "सहकार से समृद्धि" और किसानों को समृद्ध बनाने के विज़न पर बल दिया। उन्होंने BBSSL को वर्ष 2025-26 तक 20,000 नई सहकारी समितियों को जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित करने का निर्देश दिया।

बीज उत्पादन में नवीन तकनीकों पर जोर

श्री शाह ने BBSSL को बीज उत्पादन में पानी और कीटनाशकों के उपयोग को कम करने की रणनीति अपनाने और छोटे किसानों की उपज को अधिकतम करने पर काम करने का सुझाव दिया। उन्होंने बीजों की परिपक्वता अवधि को बढ़ाने और परंपरागत 'मीठे' बीजों के संग्रहण और संरक्षण पर जोर दिया।

इफ्को और कृभको को दिए निर्देश

श्री अमित शाह ने इफ्को और कृभको से पारंपरिक और हाइब्रिड बीजों का पोषण मूल्यांकन करने और अपनी प्रयोगशालाओं को आदर्श बनाने का आग्रह किया। साथ ही उन्होंने किसानों को प्रमाणित बीजों से खेती करने के लिए प्रेरित करने की अपील की।

BBSSL के प्रदर्शन और भविष्य की योजनाएं

- रबी 2024: BBSSL 6 राज्यों में 5,596 हेक्टेयर क्षेत्र में 8 फसलों की 49 किस्मों के 1,64,804 क्विंटल बीज उत्पादन का लक्ष्य लेकर चल रही है।
- वित्तीय लक्ष्य:वर्ष 2032-33 तक 18,000 करोड़ रुपए के टर्नओवर का लक्ष्य।
- अब तक का प्रदर्शन: BBSSL ने अपने परिचालन के दौरान गेहूं, मूंगफली, जई, और बरसीम जैसी फसलों के 41,773 क्विंटल बीज वितरित किए हैं, जिनका बाजार मूल्य रु.41.50 करोड़ है।

10 वर्षीय रोडमैप की योजना

श्री शाह ने बीज उत्पादन, शोध, और संवर्धन के लिए 10 साल का रोडमैप तैयार करने और इसकी नियमित समीक्षा करने का निर्देश दिया। उन्होंने सरकारी विश्वविद्यालयों और वैज्ञानिकों के सहयोग से बीज उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ाने पर बल दिया।

BBSSL ने किसानों की उपज और उनकी आय बढ़ाने के लक्ष्य के साथ कृषि क्षेत्र में सहकारिता की नई ऊंचाइयों की ओर कदम बढ़ाए हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अतिरिक्त कृषि ऋण की सीमा 1.6 लाख रु. से बढ़ाकर 2 लाख रु. की

नई दिल्ली।भारतीय रिज़र्व बैंक ने कृषि क्षेत्र की सहायता के लिए कृषि संबंधी सहायक कार्यों के लिए ऋण और बढ़ती लागतों को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अतिरिक्त कृषि ऋणों की सीमा में वृद्धि की घोषणा की है। प्रति उधारकर्ता 1.6 लाख रुपये की वर्तमान ऋण सीमा को बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया गया है।

यह निर्णय किसानों पर मुद्रास्फीति और कृषि की बढ़ती लागत के प्रभाव के कारण से किया गया है। इसका उद्देश्य किसानों को बेहतर वित्तीय पहुँच प्रदान करना है और यह सुनिश्चित करना कि उनके पास बिना प्रतिभूति की समास्या के अपनी परिचालन और विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन हों।

1 जनवरी, 2025 से प्रभावी, देश भर के बैंकों को निर्देश दिया जाता है कि वे:

- 2 लाख रुपये तक प्रति उधारकर्ता को कृषि संबंधी सहायक कार्यों सहित कृषि ऋणों के लिए अतिरिक्त प्रतिभूति और मार्जिन आवश्यकताओं को माफ करें।
- कृषक समुदाय को समय पर वित्तीय सहायता सुनिश्चित करने केलिए संशोधित दिशा-निर्देशों को शीघ्रता से लागू करें।
- बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने परिचालन क्षेत्र के किसानों और हितधारकों के बीच अधिकतम पहुंच और जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए इन परिवर्तनों का व्यापक प्रचार करें।

यह कदम विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों (क्षेत्र के 86% से अधिक) के लिए ऋण पहुंच को बढ़ाता है। ये कम उधार लागत और अतिरिक्त आवश्यकताओं को हटाने से लाभान्वित होते हैं। ऋण वितरण को सुव्यवस्थित करके। इस पहल से किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) ऋणों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है जिससे किसानों को कृषि कार्यों में निवेश करने और अपनी आजीविका में सुधार करने में सहायता मिलेगी। संशोधित ब्याज अनुदान योजना के साथ लागू 4% ब्याज दर पर 3 लाख रुपये तक के ऋण की पेशकश करते हुए, यह नीति वित्तीय समावेशन को मजबूत करती है, कृषि क्षेत्र की सहायता करती है, और ऋण-संचालित आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है। यह सतत कृषि के लिए सरकार के दीर्घकालिक दृष्टिकोण के अनुरूप है।

मात्र 5 रुपये में ग्रामीण कृषि पंप उपभोक्ताओं को मिलेंगे नवीन विद्युत कनेक्शन

'सरल संयोजन पोर्टल' के माध्यम से करना होगा आवेदन

भोपाल :मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी अपने कार्य क्षेत्र में ग्रामीण कृषि उपभोक्ताओं को अब मात्र 5 रुपये में स्थायी कृषि पंप कनेक्शन उपलब्ध कराने जा रही है। कंपनी ने कहा है कि कृषि पम्पों के कनेक्शनों की संख्या बढ़ाए जाने के लिए ऐसे कृषक जो विद्युत की उपलब्ध लाइन के समीप स्थित हैं, उनको सुविधानुसार आसानी से स्थाई कृषि पंप कनेक्शन दिया जाना सुनिश्चित किया गया है।

म.प्र.विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी नियमों के अनुसार अब निम्न दाब (एलटी) पोल से उपभोक्ताओं द्वारा स्थापित होने वाली सर्विस लाइन में सुरक्षा नियमों की जॉच कर 5 रूपए मात्र में ग्रामीण क्षेत्र में नवीन स्थाई कृषि कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। सरल संयोजन पोर्टल में उपभोक्ता का नवीन कनेक्शन का फार्म भरने की कार्यवाही भी कंपनी के मैदानी अमले द्वारा नियमानुसार की जाएगी। सुरक्षा निधि 1200 रुपये प्रति हॉर्स पॉवर उपभोक्ता के प्रथम बिल में जोड़ी जाएगी।

"पनवास में सहकारी प्रशिक्षण शिविर आयोजित, दुग्ध उत्पादन और सहकारिता पर चर्चा"

जबलपुर :सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, जबलपुर द्वारा दुग्ध सहकारी समिति मर्यादित पनवास, जिला सिवनी में एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण शिविर में सहकारिता के महत्व और समितियों में होने वाली बैठकों पर चर्चा की गई।

केंद्र के प्रशिक्षक श्री जय कुमार दुबे ने सहकारिता के उद्देश्यों और समितियों में होने वाली बैठकों के महत्त्व पर विस्तार से जानकारी दी। पशु चिकित्सक डॉ. मिश्री चंद बोपचे जी ने अपने अनुभव साझा करते हुए पशु आहार और दूध उत्पादन बढ़ाने के उपायों पर अपने विचार प्रस्तुत किए।

ग्राम पनवास के युवा सरपंच श्री देवेंद्र विसेन जी ने समिति और ग्राम से जुड़ी जानकारी दी और नए सदस्यों को समिति में सदस्यता लेने के लिए प्रेरित किया।

कार्यक्रम के समापन पर, दुग्ध संघ के परिवेक्षक श्री मनोहर बोपचे जी ने सभी उपस्थित जनों का आभार व्यक्त किया।

त्रिपुरा में सहकारिता को नई दिशा : अमित शाह ने की 8 पहलों की शुरुआत, किसानों की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने त्रिपुरा में सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने के लिए विभिन्न पहलों का शुभारंभ किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में त्रिपुरा के हर किसान और गरीब के कल्याण के लिए सहकारिता पर बल दिया जा रहा है

त्रिपुरा के किसान नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (NCOL) के साथ जुड़ें, जिससे उनकी भूमि व उत्पादों का सर्टिफिकेशन हो सके

आज NCOL और त्रिपुरा राज्य जैविक खेती विकास एजेंसी के बीच MOU सहित 8 पहलें यहां सहकारिता को गति देंगी और इससे किसानों के लिए अनेक आयाम खुलेंगे

ऑर्गेनिक खेती में कई समस्याओं का समाधान है इससे किसान की समृद्धि बढ़ती है और भूजलस्तर भी ऊपर रहता है

पहले की सरकारों में त्रिपुरा में कोऑपरेटिव घाटे में थी, 2018 के बाद से त्रिपुरा के कोऑपरेटिव लाभ अर्जित कर रहे हैं

मोदी जी ने विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना शुरू की है, अब त्रिपुरा में कोई में तहसील ऐसी नहीं बचेगी जहाँ भंडारण व्यवस्था न हो

सहकारिता मंत्रालय द्वारा लिए गए 57 इनीशिएटिव्स में से 41 इनीशिएटिव्स को लागू करने में त्रिपुरा आगे बढ़ा है, यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है

त्रिपुरा, केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने में सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने के लिए विभिन्न पहलों का शुभारंभ किया। इस अवसर पर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री प्रो (डॉ.) माणिक साहा और सहकारिता मंत्रालय के सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

अपने संबोधन में श्री अमित शाह ने कहा किप्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में त्रिपुरा के हर किसान और गरीब के कल्याण के लिए सहकारिता पर बल दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा स्थापित सहकारिता मंत्रालय का उद्देश्य सहकार से समृद्धि है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारी अर्थव्यवस्था को 11वें से 5वें स्थान पर पहुंचाया है और 2027 में हम तीसरे स्थान पर पहुंच जाएंगे। श्री शाह ने कहा कि हमारा लक्ष्य सिर्फ तीसरे स्थान पर पहुंचना नहीं है बल्कि इस प्रक्रिया में 140 करोड़ भारतीयों की सहभागिता होनी चाहिए। हर परिवार और व्यक्ति तकसमृद्धि, सुख, शिक्षा और स्वास्थ्यपहुंचने चाहिए। उन्होंने कहा कि इसे प्राप्त करने के लिए सहकारिता के सिवा कोई और रास्ता नहीं है।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि देश में 8 लाख से अधिक सहकारी संस्थाएं हैं जिनके माध्यम से 35 करोड़ से अधिक लोग सहकारिता से जुड़े हैं। अमूल, इफ्को, कृभको, नेफेड जैसी सहकारी संस्थाओं ने जन-जन को कोऑपरेटिव के साथ जोड़ने का काम किया है। उन्होंने कहा कि आज बैंकिंग, कृषि वित्तपोषण, चिकित्सा सहयोग और खाद के वितरण सहित लगभग सभी क्षेत्रों में सहकारिता मौजूद है।

श्री अमित शाह ने कहा कि हमने मोबाइल ग्रामीण मार्ट को नाबार्ड के माध्यम से शुरू किया है और 5 ज़िलों में ये मार्ट भारत ब्रांड के साथ लोगों को नाबार्ड के माध्यम से दलहन, चावल औरगेहूं का आटा सस्ते मूल्य पर उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा राज्य सहकारी बैंक की 50 प्राथमिक सहकारी समितियों को माइक्रो एटीएम उपलब्ध कराया गया है। आज त्रिपुरा में कोऑपरेटिव पैट्रोल पंप और धलाई ज़िले में एक उपभोक्ता स्टोर का भी उद्घाटन हुआ है। श्री शाह ने कहा कि त्रिपुरा राज्य सहकारी संघ का स्मार्ट प्रशिक्षण केन्द्र,NCCF के माध्यम से 500 किसानों को बीज की मिनी किट और NCOL और त्रिपुरा राज्य जैविक खेती विकास एजेंसी के बीच MOU सहित 8 पहलें आज यहां सहकारिता को गति देने के लिए की गई हैं।

केन्द्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि त्रिपुरा परंपरागत रूप से 70 प्रतिशत से अधिक ऑर्गेनिक उत्पाद पैदा करने वाला राज्य है, लेकिन यहां के उत्पादों का सर्टिफिकेशन नहीं होता है। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा के किसानों को सहकारी संस्थाओं के माध्यम से नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (NCOL)के साथ जुड़ना चाहिए जिससे उनकी भूमि और उत्पादों का सर्टिफिकेशन हो सके। श्री शाह ने कहा कि दो-तीन साल के अंदर ही NCOLकिसानों केउत्पादों का कम से कम 30% दाम ज्यादा दिलाएगा।उन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक खेती हमारी भूमि को संवर्धित और संरक्षित करती है,पर्यावरण भी अच्छा रखती है और ऑर्गेनिक उत्पाद हमारे शरीर को कई प्रकार की बीमारियों से भी बचाते हैं। उन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक खेती में कई समस्याओं का समाधान है इससे किसान की समृद्धि बढ़ती है और भूजलस्तर भी ऊपर रहता है।

श्री अमित शाह ने कहा कि केन्द्र सरकार ने अच्छे बीज उपलब्ध कराने, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए और किसानों की उपज को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने के लिए तीन राष्ट्रीय स्तर की बहुदेश्यीय सहकारी सोसाइटियां बनाई हैं। इन तीनों सोसायटियों की सदस्यता के लिए त्रिपुरा से लगभग 35 से ज्यादा सहकारी संस्थाओं नेआवेदन भेजे हैं।श्री शाह ने कहा कि अभी त्रिपुरा में 3138 अलग-अलग प्रकार की कोऑपरेटिव्स हैं जिनमें डेयरी, मत्स्य पालन, उपभोक्ता सहकारी समितियाँ, पशुधन और पोल्ट्री सहकारी समितियाँ आदि शामिल हैं। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने कोऑपरेटिव्स तो बनाईं लेकिन अपने कैडर की भर्ती का साधन समझकर नुकसान में पहुंचाया। श्री शाह ने कहा कि 2018 में यहां हमारी पार्टी की सरकार आने के बाद से त्रिपुरा के कोऑपरेटिव्सलाभ अर्जित कर रहे हैं और अब नरेन्द्र मोदी सरकार के प्रयासों से इनके लाभ में वृद्धि हो रही है।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि त्रिपुरा के किसानसहकारिता से माध्यम से अपने और अपने परिवार की समृद्धि के लिए काम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना शुरू की है जिसके तहत त्रिपुरा में कोऑपरेटिव बेसिस पर 2000 मीट्रिक टन क्षमता वाले गोदाम बनेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य की कोई तहसील ऐसी नहीं नहीं होगी जहां भंडारण की व्यवस्था न हो। श्री शाह ने कहा कि सहकारिता मंत्रालय द्वारा लिए गए 57 इनीशिएटिव्स में से 41 इनीशिएटिव्स को लागू करने में त्रिपुरा आगे बढ़ा है, जोएक बहुत बड़ी उपलब्धि है।

सर्मथन मूल्य पर हुई 7 लाख 10 हजार 320 मीट्रिक टन धान की खरीदी

भोपाल :खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अभी तक 1 लाख 5 हजार 179 किसानों से 7 लाख 10 हजार 320 मीट्रिक टन धान की खरीदी उपार्जन केन्द्रों में हो चुकी है। धान की खरीदी के लिये 1319 उपार्जन केन्द्र बनाये गये हैं। धान का उपार्जन 20 जनवरी 2025 तक किया जायेगा। धान कॉमन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2300 रूपये और धान ग्रेड-ए का 2320 रूपये है।

धान की खरीदी जिला सिवनी में 18,718, सिंगरौली 31,373, सतना 81,133, मैहर 29,721, रीवा 95,722, मऊगंज 22,809, सीधी 21,692, सागर 2222, कटनी 79,856, पन्ना 16,937, डिंडोरी 2752, दमोह 11,688, मंडला 44,883, छिंदवाड़ा 948, नरसिंहपुर 17,979, जबलपुर 28,937, बालाघाट 79,291, नर्मदापुरम 29,690, बैतूल 10,005, रायसेन 4413, सीहोर 4458, विदिशा 145, उमरिया 18,217, अनूपपुर 17,395, शहडोल 39,238, हरदा 11, भिण्ड 48, अलीराजपुर 30 और झाबुआ जिले में 9 मीट्रिक टन की जा चुकी है।

छत्तीसगढ़ में सहकारिता से समृद्धि की ओर कदम : लघु वनोपज और डेयरी विकास के लिए दो ऐतिहासिक समझौते

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की उपस्थिति में छत्तीसगढ़ में लघु वनोपज और डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए दो ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के सहकार से समृद्धि के विज़न को साकार करने की दिशा और छत्तीसगढ़ में सहकारिता क्षेत्र के विस्तार में ये समझौते महत्वपूर्ण साबित होंगे

सहकारिता से न केवल छत्तीसगढ़ में समृद्धि बढ़ रही है, बल्कि नक्सलवाद को भी मात दी जा रही है

अगले 4 वर्षों में देश के हर ज़िले में मृदा परीक्षण और ऑर्गेनिक उपज के परीक्षण के बाद सर्टिफाई किया हुआ अनाज मिलेगा

लघु वनोपज सहकारी संस्था और NCOL के बीच हुआ समझौता छत्तीसगढ़ के लाखों आदिवासी किसानों के जीवन में समृद्धि लाने वाला साबित होगा

नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों में महिलाओं को सहकारिता के माध्यम से शोषण से मुक्त कराना न सिर्फ समय की ज़रूरत है बल्कि हमारा धर्म भी है

ऑर्गेनिक उत्पादों की बढ़ती मांग के साथ मोदी सरकार किसानों के लिए वैश्विक बाजार के दरवाजे खोल रही है, जिससे उनकी आय और जीवनशैली में सुधार हो रहा है

छत्तीसगढ़ में डेयरी कोपरेटिव के लिए बहुत संभावनाएं उपलब्ध हैं, यहां हर गांव में डेयरी कोऑपरेटिव बननी चाहिए

नई दिल्ली। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की उपस्थिति में छत्तीसगढ़ में लघु वनोपज और डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए दो ऐतिहासिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के सहकार से समृद्धि के विज़न को साकार करने की दिशा और छत्तीसगढ़ में सहकारिता क्षेत्र के विस्तार में ये समझौते महत्वपूर्ण साबित होंगे।

इस अवसर पर अपने संबोधन में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि आज छत्तीसगढ़ में सहकारिता के माध्यम से दो अच्छी शुरूआत हो रही हैं। उन्होंने कहा कि आज खानपान में विषैले तत्वों की मात्रा बढ़ने के कारण कई प्रकार की गंभीर बीमारियां लोगों को हो रही हैं। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ की आबादी वाले भारत जैसे विशाल देश में बीमारियों का इलाज करने की जगह बीमारियां न हों, ऐसा खानपान लाना ज़रूरी है। श्री शाह ने कहा कि इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में ऑर्गेनिक खेती पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की शुरूआत की गई है। उन्होंने कहा कि एक ज़माने में कहा जाता था कि ऑर्गेनिक खेती करने से किसानों की आय कम हो जाएगी। उन्होंने कहा कि गुजरात जैसे राज्यों में लाखों किसानों ने ऑर्गेनिक खेती को स्वीकार किया है और उनकी आय में वृद्धि हुई है। श्सहकारिता मंत्री ने कहा कि गुजरात के किसान, देसी गाय के गोबर को एक विशिष्ट प्रक्रिया से ऑर्गेनिक खाद में बदल कर एक गाय से 21 एकड़ खेती सफलतापूर्वक कर बिना किसी रासायनिक खाद या पैस्टीसाइड डाले सवा गुना उत्पादन कर रहे हैं।

श्री अमित शाह ने कहा कि आज बाज़ारों में कई प्रकार के ऑर्गेनिक कहलाने वाले उत्पाद मिलते हैं लेकिन उनके सर्टिफिकेशन की कोई व्यवस्था नहीं है। उन्होंने कहा कि किसानों को अपनी ऑर्गेनिक उपज का उचित दाम नहीं मिलता था क्योंकि ये पता करना मुश्किल था कि ये उत्पाद ऑर्गेनिक है या नहीं और एक विश्वास का संकट खड़ा हो गया था। श्री शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने बहुद्देश्यीय राष्ट्रीय स्तर की सहकारी संस्था NCOL की स्थापना की। उन्होंने कहा कि आज दो बड़े कोऑपरेटिव ब्रांड, भारत और अमूल, विश्वसनीय तरीके से ऑर्गेनिक फूड सप्लाई कर रहे हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि अगले 4 वर्षों में देश के हर ज़िले में मृदा परीक्षण और ऑर्गेनिक उपज के परीक्षण के बाद सर्टिफाई किया हुआ अनाज देश के बाज़ार में मिलेगा। उन्होंने कहा कि आज देश में चावल और हल्दी जैसी 16 भारत ब्रांड के ऑर्गेनिक उत्पाद मिल रहे हैं। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि आज यहां पर जनजाति समूह के वनोपज सहकारी संस्था और NCOL के बीच एक समझौता हुआ है। उन्होंने कहा कि इस समझौते के तहत उत्पाद का सर्टिफिकेशन किया जाएगा जिससे बाज़ार में उत्पाद का अच्छा दाम मिलेगा। श्री शाह ने कहा कि ये समझौता छत्तीसगढ़ के लाखों आदिवासी किसानों के जीवन में समृद्धि लाने वाला साबित होगा।

श्री अमित शाह ने कहा कि आज हुआ दूसरा समझौता छत्तीसगढ़ सरकार, छत्तीसगढ़ दुग्ध संघ और NDDB के बीच हुआ है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में डेयरी कोपरेटिव के लिए बहुत संभावनाएं उपलब्ध हैं और हमें ये सुनिश्चित करना है कि राज्य के हर गांव में डेयरी कोऑपरेटिव बने। श्री शाह ने कहा कि नक्सलवाद से मुक्त हुए क्षेत्रों में पिछड़े समाज की महिलाओं को सहकारिता के माध्यम से डेयरी के साथ जोड़कर उन्हें शोषण से मुक्त कराना न सिर्फ समय की ज़रूरत बल्कि हमारा धर्म भी है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की महिलाओं की भलाई सहकारिता से ही हो सकती है। उन्होंने कहा कि एक आदर्श कोऑपेरेटिव व्यवस्था बनाने के लिए छत्तीसगढ़ में बहुत संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि यहां कोऑपरेटिव व्यवस्था खड़ी करने की ज़िम्मेदारी राज्य सरकार की है।

केन्द्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि NDDB, छत्तीसगढ़ दुग्ध उत्पादन संघ को हरसंभव सहायता देगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में मात्र 5 लाख किलोग्राम प्रतिदिन के दुग्ध उत्पादन के लक्ष्य को बढ़ाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इसके लिए गाय-भैंसों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है। श्री शाह ने कहा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को पंजीकरण की संख्या इस प्रकार बढ़ानी चाहिए कि हर गांव तक सहकारिता पहुंचे और हर किसान सहकारी संस्था का सदस्य बने।

श्री अमित शाह ने कहा कि आज हुए दोनों समझौते आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ की समृद्धि, शांति और सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। उन्होंने कहा कि डेयरी कोऑपरेटिव हर गांव में पहुंचने से गांवों का परिदृश्य बदलते हुए देर नहीं लगेगी और राज्य में सहकारिता के विस्तार के लिए केन्द्रीय सहकारिता मंत्रालय किसी भी प्रकार की सहायता देने में छत्तीसगढ़ को प्राथमिकता देगा। उन्होंने कहा कि सहकारिता से न केवल छत्तीसगढ़ में समृद्धि बढ़ रही है, बल्कि नक्सलवाद को भी मात दी जा रही है। लघु वनोपज संघ और राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के बीच हुए समझौते का मुख्य उद्देश्य राज्य में जनजातीय समुदायों द्वारा एकत्र किए गए वनोपजों को संगठित करना, उनका प्रसंस्करण करना और बेहतर बाजार उपलब्ध कराना है। छत्तीसगढ़ के जैविक प्रमाणित उत्पाद जैसे जंगली वन शहद, इमली, काजू, चिरौंजी, महुआ और मोटे अनाज को "भारत ऑर्गेनिक्स" ब्रांड के तहत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बढ़ावा दिया जाएगा। यह पहल जनजातीय परिवारों की आय में वृद्धि के साथ-साथ वनोपज के संग्रहण और प्रसंस्करण में शामिल स्वयं सहायता समूहों को मजबूती प्रदान करेगी। जैविक प्रमाणित उत्पादों के लिए स्थायी संग्रहण प्रथाओं को भी इस समझौते के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ सरकार और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) के बीच हुए समझौते का उद्देश्य राज्य के डेयरी सहकारी क्षेत्र को सशक्त बनाना और दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना है। राज्य में वर्तमान में कार्यरत 650 डेयरी सहकारी समितियों को विस्तारित कर 3850 तक बढ़ाया जाएगा। साथ ही, 3200 नई बहुउद्देशीय प्राथमिक डेयरी सहकारी समितियों का गठन किया जाएगा। दूध संकलन की क्षमता को 79 हजार किलोग्राम से बढ़ाकर 5 लाख किलोग्राम प्रतिदिन और दूध प्रसंस्करण क्षमता को तीन गुना बढ़ाकर 4 लाख लीटर प्रतिदिन किया जाएगा। तरल दूध की बिक्री को 10 गुना बढ़ाकर 4 लाख लीटर प्रतिदिन तक ले जाने का लक्ष्य है।

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) इस परियोजना के तहत प्रबंधकीय सहायता प्रदान करेगा और डेयरी संयंत्रों, कैटल फीड प्लांट और मिनरल मिक्स्ड प्लांट के लिए किसी भी तकनीकी सेवा शुल्क (TSF) चार्ज नहीं लेगा। इस परियोजना को केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं, NABARD के ऋण और राज्य सरकार के योगदान के माध्यम से वित्तपोषित किया जाएगा।

वन समितियों में सहकार से समृद्धि के खुलेंगे द्वार : मंत्री श्री सारंग

प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का भाव, भारतीय समाज की सभ्यता एवं विरासत : आयुष मंत्री श्री परमार

अंतर्राष्ट्रीय वन मेला-2024 का हुआ समापन

भोपाल : खेल एवं युवा कल्याण, सहकारिता मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वन मेला वनों, वन उत्पादों के प्रति जागरूकता को बढ़ाने के साथ ही दूरस्थ अंचलों के ग्रामीणों को सतत आजीविका के साधन उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण मंच है। वन मेले से लघु वनोपजों के संग्रहण एवं विक्रय के नये अवसर मिलते हैं, जो विक्रय श्रृंखला के निर्माण में सहायक होते हैं। मेले में वैद्यों द्वारा आयुर्वेद का ज्ञान देने के साथ वन से प्राप्त जड़ी-बूटियों को प्रदर्शित किया जाता है। मंत्री श्री सारंग ने कहा कि भारतीय परम्परा में प्रकृति के साथ ज्ञान एवं व्यवहार अद्भुत एवं आश्चर्यजनक रहा है। उन्होंने सहकार से समृद्धि के साथ संस्कार से सहकार की बात कही। मंत्री श्री सारंग लाल परेड ग्राउण्ड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वन मेले के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे।

मंत्री श्री सारंग ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वन मेले को और अधिक भव्यता प्रदान की जायेगी। उन्होंने कहा कि वनोपज के संग्रहण और विक्रय में समितियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। वनांचलों में रहने वालों के सशक्तिकरण के लिये सहकार अत्यंत आवश्यक है। इससे ही वनों में रहने वालों का आर्थिक सशक्तिकरण होगा। मंत्री श्री सारंग ने कहा कि वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के रूप में मनाया जायेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश को सशक्त बनाने के लिये सहकार आंदोलन चलाया जायेगा। सहकार आंदोलन से सशक्त समाज का निर्माण होता है। मंत्री श्री सारंग ने अंतर्राष्ट्रीय वन मेले के सफल आयोजन पर बधाई दी।

उच्च शिक्षा एवं आयुष मंत्री श्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का भाव, भारतीय समाज की सभ्यता एवं विरासत है। मंत्री श्री परमार ने कहा कि वन मेला भारतीय सम्पदा, सभ्यता एवं ज्ञान परम्परा को निरंतर आगे बढ़ाने के संकल्प का उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने कहा कि वन मेला का उद्देश्य मात्र प्रदर्शन नहीं, बल्कि जीवन पद्धति का व्यापक दृष्टिकोण है। आयुर्वेद भारत की पुरातन चिकित्सा पद्धति है, जो वन औषधियों पर आधारित है। हमारे देश में कृषि के बाद बड़ी आबादी आजीविका के लिये वनोपज पर ही निर्भर है। उनका उद्देश्य वनोपज का दोहन नहीं, बल्कि अपनी आवश्यकता अनुसार उपयोग के साथ वनों का संरक्षण करना भी है।

मंत्री श्री परमार ने कहा कि हमारे पूर्वज वनस्पती का महत्व जानते थे, इसलिये प्रकृति के संरक्षण के भाव से परम्परा एवं मान्यताएँ स्थापित कीं। उन्होंने कहा कि प्रकृति के अंग नदी, पेड़, पहाड़ एवं सूर्य आदि समस्त के प्रति कृतज्ञता का भाव इनके संरक्षण एवं लोक कल्याण निहित हैं। मंत्री श्री परमार ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आयुर्वेद का आगे बढ़ाने का संकल्प जन-आंदोलन बन रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाला समय आयुर्वेद का है।

मंत्री द्वय ने वन मेले में वनोपज एवं वन औषधियों के विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन किया। उन्होंने वनोपज संघ की स्मारिका "व्यापार एवं विकास" एवं ईको-टूरिज्म की "अनुभूति" पुस्तिका का विमोचन किया। अंतर्राष्ट्रीय वन मेले में उत्कृष्ट प्रदर्शनी, जिला यूनियन, शासकीय एवं निजी स्टॉल, वन-धन केन्द्र एवं आयुर्वेदिक महाविद्यालयों के स्टॉल के उत्कर्ष प्रदर्शन के लिये प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया।

मंत्री श्री सारंग, मंत्री श्री परमार और भोपाल नगर निगम मेयर श्रीमती मालती राय को स्मृति-चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव श्री अशोक वर्णवाल, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख श्री असीम श्रीवास्तव, प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ श्री विभाष कुमार ठाकुर, विभागीय अधिकारी और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

(पृष्ठ 1 का शेष)

सहकारिता के नए युग की शुरुआत....

उन्होंने कहा कि ये प्रशिक्षण मॉड्यूल हर ज़िला सहकारी रजिस्ट्रार की ज़िम्मेदारी बने और पैक्स के सचिव एवं कार्यकारिणी के सदस्यों का अच्छा प्रशिक्षण सुनिश्चित हो।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि आज यहां 10 सहकारी समितियों को RuPay Kisan Credit Card, माइक्रो ATM का वितरण किया गया है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत आने वाले दिनों में हर प्राथमिक डेयरी को माइक्रो- एटीएम दिया जाएगा। माइक्रो एटीएम और RuPay Kisan Credit Card हर किसान को कम खर्च पर ऋण देने का काम करेगा। श्री शाह ने कहा कि पैक्स के विस्तार के लिए विज़िबिलिटी, रेलेवेंस, वायबिलिटी और वायब्रेंसी का ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि पैक्स में 32 कामों को जोड़कर इसे विजिबल और वायबल बनाया है। उन्होंने कहा कि गांव में Common Service Centre (CSC) जब पैक्स बन जाता है तो गांव के हर नागरिक को किसी न किसी रूप में पैक्स के दायरे में आना पड़ता है, इस प्रकार हमने इसकी रेलेवेंस भी बढ़ाई है। श्री शाह ने कहा कि जब पैक्स गैस वितरण, भंडारण, पेट्रोल वितरण आदि का काम करते हैं, तो उनकी वायब्रेंसी अपने आप बढ़ जाती है और पैक्स के बहुद्देश्यीय होने से पैक्स का जीवन भी लंबा होने की पूरी संभावना रहती है। उन्होंने कहा कि यह एक बहुद्देशीय कार्यक्रम है, जिससे किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने का एक मजबूत प्रयास होगा।

श्री अमित शाह ने कहा कि कंप्यूटराइजेशन और टेक्नोलॉजी से पैक्स में पारदर्शिता आएगी, सहकारिता का जमीनी स्तर पर विस्तार होगा और ये महिलाओं और युवाओं के रोजगार का माध्यम भी बनेगा। उन्होंने कहा कि पैक्स, कृषि संसाधनों की सरल उपलब्धता भी सुनिश्चित करेगा। श्री शाह ने कहा कि हमारी तीन नई राष्ट्रीय स्तर की कोऑपरेटिव्स के माध्यम से पैक्स, ऑर्गेनिक उत्पादों, बीजों और एक्सपोर्ट के साथ किसानों की समृद्धि के रास्ते भी खोलेगा। उन्होंने कहा कि इससे सामाजिक और आर्थिक समानता भी आएगी क्योंकि नए मॉडल बायलॉज में महिलाओं, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों की भागीदारी सुनिश्चित की है, जिससे सामाजिक समरसता भी बढ़ेगी।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार ने लक्ष्य रखा है कि अगले पांच साल में 2 लाख नए पैक्स का गठन करेंगे। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि 5 साल से पहले ही हम दो लाख पैक्स का गठन कर लेंगे। उन्होंने बताया कि पहले चरण में नाबार्ड 22,750 पैक्स और दूसरे चरण में 47,250 पैक्स बनाएगा, इसी प्रकार एनडीडीबी 56,500 नई समितियाँ बनाएगा और 46,500 मौजूदा समितियों को सुदृढ़ बनाएगा। एनएफडीबी 6,000 नई मत्स्य सहकारी समितियाँ बनाएगा और 5,500 मौजूदा मत्स्य सहकारी समितियों का सशक्तिकरण करेगा। इनके अलावा राज्यों के सहकारी विभाग 25000 पैक्स बनाएंगे। श्री शाह ने कहा कि नए मॉडल बायलॉज के साथ अब तक 11,695 नई प्राथमिक सहकारी समितियां पंजीकृत हुई हैं, जो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि 2 लाख नए पैक्स बनने के बाद फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस के माध्यम से किसानों की उपज को वैश्विक बाजार में पहुंचाना बड़ा सरल हो जाएगा।

बोरी में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन

इंदौर। सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, इंदौर द्वारा "बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि सहकारी सोसाइटी, बोरी", तहसील-जोबट, जिला-अलीराजपुर में एक दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्थानीय कृषकों और समिति के सदस्यों को सहकारिता के सिद्धांतों, उसके लाभों और नवाचारों के बारे में जानकारी प्रदान करना था। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान सहकारिता की पृष्ठभूमि पर चर्चा की गई, जिसमें बताया गया कि किस प्रकार सहकारिता से समृद्धि प्राप्त की जा सकती है। इसके बाद, बहुउद्देश्यीय सहकारी समितियों के लाभों पर विस्तार से चर्चा की गई, जिसमें यह बताया गया कि बहुउद्देशीय समितियाँ कृषि, वित्तीय और सामाजिक दृष्टिकोण से समुदायों को कैसे सशक्त बना सकती हैं।

कार्यक्रम में सहकारिता में नवाचारों की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी ध्यान केंद्रित किया गया, जिससे कि समितियाँ आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके अधिक प्रभावी और सक्षम बन सकें। इसके अलावा, विभिन्न सहकारी समितियों द्वारा किए जा रहे नवाचारों को उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत किया गया, जिससे स्थानीय सदस्य उन्हें अपने काम में लागू कर सकें।

इस कार्यक्रम में समिति के सहायक प्रबंधक श्री मगन सिंह चौहान, कंप्यूटर ऑपरेटर श्री मनीष, कृषक बंधु और सम्माननीय सदस्य उपस्थित थे। कार्यक्रम के समापन पर ऑपरेटर श्री मनीष ने संस्था की ओर से सभी का आभार व्यक्त किया।

मध्यप्रदेश वन संपदा की दृष्टि से समृद्ध राज्य : राज्यपाल श्री पटेल

मध्यप्रदेश के वन, वनोपज और वन्य-प्राणी प्रदेश की पहचान : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने किया 7 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय वन मेले का शुभारंभ

भोपाल :राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने कहा है कि मध्यप्रदेश वन संपदा की दृष्टि से समृद्ध राज्य है। यहां पर औषधीय जड़ी-बूटियों का समृद्ध भंडार है। कोविड महामारी ने विश्व को आयुर्वेद के महत्व से पुन: परिचित कराया है। उन्होंने महामारी के दौरान मरीजों के ईलाज के लिए आयुर्वेदिक काढ़ा वितरण कार्य के लिए प्रदेश सरकार की सराहना की। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि वन मेले का आयोजन, वन संसाधनों की महत्ता, उनके संरक्षण और संवर्धन की जागरूकता प्रसार की दिशा में सुखद संकेत है। राज्यपाल श्री पटेल 10वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेले के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

राज्यपाल श्री पटेल ने शुभारंभ अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव के साथ हितग्राहियों को लघु वनोपज संघ अंतर्गत प्रोत्साहन पारिश्रमिक राशि का वितरण किया। वन एवं राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ द्वारा 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का लाल परेड ग्राउंड भोपाल में 17 से 23 दिसंबर तक आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने की।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का अपना महत्व है, लेकिन वनों से प्राप्त औषधियों की विशेष उपयोगिता है। कोरोना के कठिन समय में आयुर्वेद ने लोगों के जीवन बचाने में मदद की। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा दिया है। अब चिकित्सा जगत में फिर से आयुष का महत्व बढ़ा है। वन मेले जैसे आयोजन इस नाते बहुत महत्व रखते हैं। वास्तव में यह अंतर्राष्ट्रीय वन मेला अनोखा है। इस मेले की शुरूआत 2001 से हुई और धीरे-धीरे यह प्रदेश से आगे बढ़कर देश तक और फिर वैश्विक हो गया। मेले ने अपनी अलग पहचान बनाई है। आम तौर पर वन और वन-सम्पदा से मेलों का इतना विस्तार होना हम सब के लिए गौरव की बात है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव मंगलवार को भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में 10वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेले को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमारे प्रदेश की वन सम्पदा विशिष्ट है। हम तो सौभाग्यशाली हैं कि हमारे यहां वन सम्पदा, वनों का आंतरिक वातावरण भी विशेष है और प्रदेश के वनों की अलग पहचान है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वन्य प्राणी हमारे जंगल के आभूषण होते हैं, जिनके कारण जंगल की शोभा होती है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में मध्यप्रदेश चीतों को पुनर्स्थापित करने में सफलता प्राप्त हुई है। वन्य जीव परम्परा में सभी प्रकार के टाइगर, तेंदुआ, चीता का महत्व है। टाइगर में हम देश में नम्बर वन पर है। वास्तव में पुनर्स्थापना में मध्यप्रदेश की भूमि का चयन होना हमारे लिये गर्व की बात है। जो चीते सम्पर्ण एशिया से ही गायब हो गए थे। इसके लिए वन विभाग के अधिकारी-कर्मचारी भी बधाई के पात्र हैं। वन विभाग ने यह अनोखा प्रयोग किया है। इस प्रयोग के अच्छे परिणाम उनके लिये आ रहे हैं। धीरे-धीरे हमारे यहाँ नए-नए मेहमान आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है वे कि मध्यप्रदेश का वातावरण अनुकूल हो गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश के वनवासी भी वनों की रक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में मध्यप्रदेश और राजस्थान के बीच सिंचाई, उद्योग क्षेत्र और पेयजल की दृष्टि से महत्वपूर्ण पार्वती-काली सिंध-चम्बल परियोजना के लिए आज जयपुर में त्रिपक्षीय अनुबंध का अवसर दिया। केंद्र सरकार द्वारा परियोजना के लिए 90 प्रतिशत राशि प्रदान की जाएगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि 11 दिसम्बर से प्रारंभ हुए जनकल्याण पर्व की गतिविधियां 26 दिसम्बर तक चलेंगी। प्रतिदिन प्रदेशवासियों को एक नई सौगात दी जा रही है। हाल ही में राजधानी के निकट लोकार्पित अभ्यारण का नाम पुरातत्वशास्त्री डॉ. विष्णु श्रीधर वाकणकर के नाम पर किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने नागरिकों से आहवान किया कि वे वन मेले में प्रदर्शित औषधियों को खरीदें और लाभ प्राप्त करें। उन्होंने वन विभाग को श्रेष्ठ आयोजन के लिए बधाई दी। प्रारंभ में राज्यपाल श्री पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने रायसेन, विदिशा, सिवनी और अन्य जिलों से आए 9 तेंदूपत्ता संग्राहकों को वर्ष 2023 के तेंदूपत्ता संग्रहण कार्य की बोनस राशि के चेक प्रदान किए।

वन्य राज्य मंत्री श्री दिलीप अहिरवार ने कहा कि यह मेला दिव्यता और भव्यता का प्रतीक है। राज्य सरकार ने तेंदूपत्ता संग्राहकों का मानदेय तीन हजार रुपए से बढ़ाकर 4 हजार रुपए प्रति मानक बोरा किया है। विभाग में अनुकंपा नियुक्ति, दुर्घटना पर राहत राशि के महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। कार्यक्रम में विधायक श्री भगवान दास सबनानी, अपर मुख्य सचिव वन श्री अशोक बर्णवाल और प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख श्री असीम श्रीवास्तव भी उपस्थित थे। प्रारंभ में लघुवनोपज संघ के एमडी श्री विभाष ठाकुर ने स्वागत भाषण दिया। अतिथियों को बांस की टोकरी एवं अन्य वन्य उत्पाद, स्मृति चिन्ह के रूप में दिए गए।

राज्यपाल श्री पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने वन मेले में विभिन्न स्टाल्स का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जनजातीय समाज के पारम्परिक वाद्य यंत्रों को बजाते हुए जनजातीय लोक कलाओं से जुड़े कलाकार दल से भेंट एवं चर्चा की।

दमदम में एक दिवसीय सहकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफल आयोजन

सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, इंदौर द्वारा प्राथमिक कृषि सहकारी संस्था मर्यादित, दमदम, जिला-आगर (मालवा) में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सहकारिता के सिद्धांतों, उसकी पृष्ठभूमि और नवाचारों के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान करना था। प्रशिक्षण कार्यक्रम में सहकारिता के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। पहले सत्र में सहकारिता की पृष्ठभूमि और इतिहास के बारे में जानकारी दी गई, जिससे सभी प्रतिभागियों को सहकारिता के महत्व और उसके विकास के बारे में समझने का अवसर मिला। इसके बाद, सहकारिता के सिद्धांतों को विस्तार से समझाया गया, जिनमें सहयोग, समानता, और न्याय के सिद्धांत प्रमुख थे।

तीसरे सत्र में सहकारिता में नवाचारों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें कृषि क्षेत्र में सहकारी संस्थाओं द्वारा अपनाए गए आधुनिक तकनीकों और प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी दी गई। इस सत्र का उद्देश्य सदस्यों को सहकारी समितियों के माध्यम से अपनी उत्पादन प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए प्रेरित करना था।

कार्यक्रम में संस्था के विभिन्न पदाधिकारियों और सदस्यगणों की भागीदारी रही। इस दौरान समिति के प्रबंधक श्री रमेशचंद्र जायसवाल, सहायक प्रबंधक श्री नारायण गोस्वामी, कम्प्यूटर ऑपरेटर श्री जगदीशचंद्र लौहार, कृषक बंधु और अन्य सम्माननीय सदस्य उपस्थित रहे।

किसानों को समय पर कराएं भुगतान और उपार्जित धान का जल्द करें परिवहन : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने धान उपार्जन की समीक्षा कर खुले में पड़े धान को तत्काल सुरक्षित करने के दिए निर्देश

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि जिन किसानों का धान उपार्जित कर लिया गया है, उन्हें कम से कम समय में भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएं। प्रक्रिया को सरल कर तीन से चार दिनों में उपार्जन राशि का भुगतान कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि मौसम को देखते हुए खुले में पड़े धान का जल्द से जल्द परिवहन कराएं और इसे बारिश से बचाएं। उन्होंने कहा कि गोडाऊन परिसर में भी यदि उपार्जित धान खुले में रखा है तो उसे जल्द से जल्द अंदर रखवा लिया जाए।

बैठक में सहकारिता मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग, किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री एदल सिंह कंषाना, अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा, अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त श्री मोहम्मद सुलेमान, अपर मुख्य सचिव सहकारिता श्री अशोक बर्णवाल, प्रमुख सचिव खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण श्रीमती रश्मि अरूण शमी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

धान को बारिश से बचाने की तुरंत व्यवस्था करें

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जिन सहकारी समितियों में धान खुले आसमान के नीचे रखा है, खराब मौसम की आशंका को देखते हुए उपार्जित धान को बारिश से बचाने के लिए समितियां तत्काल तिरपाल आदि से खुले में पड़े धान को ढंक लें। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से कहा कि वे किसानों से यह आग्रह करें कि मौसम को देखते हुए वे कुछ दिन रूककर या मौसम साफ होने पर ही अपना धान उपार्जन के लिए लेकर आएं। मौसम यदि ज्यादा दिन तक खराब रहता है तो सरकार धान उपार्जन की तय अवधि बढ़ाने पर भी विचार करेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अधिकारियों से कहा कि वे धान मिलर्स को निर्देशित करें कि वे भी अपने धान का जल्द से जल्द उठाव करा लें। उन्होंने नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारियों से कहा कि वे उपार्जित धान का तत्काल परिवहन कराकर इन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाएं और आवश्यकतानुसार प्रबन्ध करें।

उपार्जित धान मिलर्स को देने का प्रयास करें

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि उपार्जन प्रक्रिया को सरल बनाया जाएं, ताकि तय समय-सीमा तक अधिकतम किसानों का धान उपार्जन हो सके। किसानों से जो धान उपार्जित किया जा रहा है, उन्हें अधिकाधिक मात्रा में धान मिलर्स को ही देने का प्रयास करें, इससे धान मिलिंग की प्रक्रिया पर लगने वाला समय, धन और श्रम बचेगा।

धान परिवहन हेतु अनुबंधित परिवहनकर्ताओं के माध्यम से अधिक से

अधिक वाहन लगाए जाए एवं आवश्यक हो तो अन्य परिवहनकर्ता/वाहनों को अधिग्रहण कर धान का परिवहन कराया जाए। गोदाम स्तरीय उपार्जन केन्द्र पर खुले में भण्डारित धान को सहकारी समितियों के माध्यम से गोदाम में धान की स्टेकिंग कराई जाए। समर्थन मूल्य पर धान विक्रय करने वाले किसानों के शीघ्र भुगतान हेतु स्वीकृति पत्रक शीघ्रता से जारी कराए जाए। भारत सरकार द्वारा एफएक्यू मापदण्ड अनुसार धान का उपार्जन किया जाए जिसकी मॉनिटरिंग हेतु अन्य विभाग के अमले को भी लगाया जाए।

प्रमुख सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति द्वारा बताया गया कि इस वर्ष 7.72 लाख किसानों ने धान उपार्जन के लिए पंजीयन कराया है, जो गत वर्ष 2023-24 (7.27 लाख) की तुलना में अधिक है। इस वर्ष प्रदेश में 1393 धान उपार्जन केन्द्र बनाए गए हैं, जिसमें अब तक 22.86 लाख मीट्रिक धान का उपार्जन हो चुका है। अब तक 3.48 लाख किसान अपना धान बेच चुके हैं। जिन किसानों से उपार्जन हो चुका है, उन्हें न्यूनतम समय में भुगतान की व्यवस्था की जा रही है। 26 दिसम्बर तक 45 लाख मीट्रिक टन धान कॉमन (ग्रेड ए श्रेणी का) उपार्जित किया जा चुका है। जिन किसानों से धान उपार्जन किया गया है, उन्हें उपार्जन मूल्य के रूप में 1,961 करोड़ रूपए का भुगतान किए जा चुके हैं। प्रदेश में बारदाने की कोई कमी नहीं है। उपार्जित धान का परिवहन और भंडारण भी समुचित तरीके से किया जा रहा है। प्रदेश में कुल 674 अनुबंधित मिलर्स हैं। इनके द्वारा अब तक 3.36 लाख मीट्रिक टन उपार्जित धान का उठाव कर लिया गया है।

किसानों को एसएमएस में माध्यम से सूचित किया जा रहा है कि आगामी30, 31 दिसम्बर और एक जनवरी को धान की खरीदी स्थगित रहेगी। धान खरीदी की अंतिम तिथि 20 जनवरी से बढ़ाकर 23 जनवरी कर दी गयी है। जिन किसानों के स्लॉट धान विक्रय के लिए बुक थे, उसकी अवधि 5 दिन बढ़ा दी गयी है। उन्हें पुन: स्लॉट बुक करने की जरूरत नहीं है।

ई-मंडी योजना एक जनवरी से बी-क्लास की 41 मंडियों में होगी शुरू : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

किसान अपने मोबाइल से बना सकेंगें प्रवेश पर्ची

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि ई-मंडी योजना एक जनवरी 2025 से प्रदेश की बी-क्लास की 41 मंडियों में विस्तारित की जा रही है। मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड (मंडी बोर्ड) अपनी महत्वपूर्ण ई-मंडी योजना का विस्तार कर रहा है। पूर्व से ई-मंडी योजना 42 मंडियों में क्रियाशील है। मंडियों को सर्वसुविधायुक्त बनाने के लिये प्रदेश में निरंतर कार्य किया जा रहा है।

ई-मंडी योजना से किसान मंडियों में अपनी उपज के विक्रय के लिये स्वयं अपनी पर्ची बना सकेंगे। मंडी ऐप से किसानों को सुविधा होगी। उन्हें उपज विक्रय के लिये या प्रवेश पर्ची के लिये लाईन में नहीं लगना होगा। ई-मंडी योजना के तहत मंडी प्रांगण में प्रवेश से लेकर नीलामी, तौल तथा भुगतान तक की कार्यवाही कंप्यूटराइज्ड रहेगी। मंडियों को हाईटेक बनाया जा रहा है। लक्ष्य रखा गया है कि 01 अप्रैल 2025 से सभी 259 मंडियां ई-मंडी के रूप में कार्य करें।

मोबाइल ऐप से प्रक्रिया होगी सरल

मंडी ऐप के द्वारा किसान भाइयों के लिये प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। किसानों को यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है कि वह मंडी आने से पहले मंडी में अपनी प्रवेश पर्ची स्वयं अपने मोबाइल से बना सकते हैं। एक बार प्रवेश पर्ची बन जाने पर बार-बार उन्हें अपना संपूर्ण डाटा मंडी में देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। प्रवेश पर्ची बन जाने से किसान सीधे मंडी प्रांगण के नीलामी स्थलों पर जाकर अपनी कृषि उपज की नीलामी करा सकते हैं।

नीलामी की कार्यवाही भी मिलेगी मोबाइल पर

नीलामी की कार्यवाही की जानकारी किसानों को मोबाइल पर भी प्राप्त होगी। तुलावटी भाईयों को ई-मंडी योजना का प्रशिक्षण दिया गया है। वे एंड्रॉयड मोबाइल पर की गई तौल का फाइनल वजन दर्ज करेंगे और उन्हें कोई भी जानकारी लिखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। साथ ही व्यापारी साथियों को भी भुगतान पत्रक बनाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ई-मंडी योजना में व्यापारी की आईडी पर रेडीमेड भुगतान पत्रक प्रदर्शित होगा। व्यापारी को उनके द्वारा किसानों को किये जा रहे भुगतान की सिर्फ एंट्री ही करनी होगी।

रियल टाइम होगा उपज रिकार्ड का संधारण

ई-मंडी योजना से किसानों द्वारा मंडी में विक्रय की जा रही कृषि उपज का रिकार्ड संधारण रियल टाइम ऑनलाइन होगा। इससे मंडियों में भीड़-भाड़ भी नहीं होगी और असुविधा भी नहीं होगी। किसान भाइयों को प्रवेश, अनुबंध, तौल तथा भुगतान करने के बाद उनके मोबाइल पर एसएमएस तथा व्हाट्सएप मैसेज प्राप्त होगा। किसानों को यह जानकारी रहेगी कि उनकी उपज किस व्यापारी द्वारा कितने दाम पर खरीदी गई है।

ई-मंडी योजना में बी-श्रेणी की 41 मंडिया

1. कृ.उ.म.स. बैरसिया,
2. कृ.उ.म.स. भैरूंदा,
3. कृ.उ.म.स. औबेदुल्लागंज,
4. कृ.उ.म.स. रायसेन,
5. कृ.उ.म.स. सिरोंज,
6. कृ.उ.म.स. ब्यावरा,
7. कृ.उ.म.स. पचौर,
8. कृ.उ.म.स. नरसिंहगढ़,
9. कृ.उ.म.स. कुरावर,
10. कृ.उ.म.स. खिरकिया,
11. कृ.उ.म.स. नर्मदापुरम,
12. कृ.उ.म.स. सांवेर,
13. कृ.उ.म.स. महू,
14. कृ.उ.म.स. मनावर,
15. कृ.उ.म.स. कुक्षी,
16. कृ.उ.म.स. धामनोद,
17. कृ.उ.म.स. सनावद,
18. कृ.उ.म.स. भीकनगांव,
19. कृ.उ.म.स. बुरहानपुर,
20. कृ.उ.म.स. महिदपुर,
21. कृ.उ.म.स. तराना,
22. कृ.उ.म.स. पिपल्या,
23. कृ.उ.म.स. सैलाना,
24. कृ.उ.म.स. शाजापुर,
25. कृ.उ.म.स. दतिया,
26. कृ.उ.म.स. कुम्भराज,
27. कृ.उ.म.स. मुंगावली,
28. कृ.उ.म.स. कोलारस,
29. कृ.उ.म.स. श्योपुरकलां,
30. कृ.उ.म.स. बीना,
31. कृ.उ.म.स. खुरई,
32. कृ.उ.म.स. हरपालपुर,
33. कृ.उ.म.स. निवाड़ी,
34. कृ.उ.म.स. शहपुरा "भिटोनी",
35. कृ.उ.म.स. सौंसर,
36. कृ.उ.म.स. गाडरवाड़ा,
37. कृ.उ.म.स. करेली,
38. कृ.उ.म.स. नरसिंहपुर,
39. कृ.उ.म.स. गोटेगांव
40. कृ.उ.म.स. सिवनी और
41. कृ.उ.म.स. नागोद।

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक गणेश प्रसाद मांझी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय परिमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई-8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : गणेश प्रसाद मांझी डॉक पंजीयन क्रमांक : म.प्र./भोपाल/357/2021-23 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2926159, 2926160, इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।